

सम्पादकीय

सामाजिक सुरक्षा की चुनौती
: महंगाई का चौतरफा असर

यदि खुदरा मुद्रास्फीति जल्द ही कम नहीं होती है और आर्थिक सुधार में देरी होती है, तो सरकार को सबसे कमज़ोर लोगों को अधिक से अधिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। ऐसे अनिश्चित माहौल में जब मौसम की चरम स्थितियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो हमारे लिए जलवायु परिवर्तन उतना ही महत्वपूर्ण कारक होना चाहिए और खाद्यान्न के बारे में हमारी चर्चा में मौसम की चरम घटनाओं से निपटने की आवश्यकता शामिल होनी चाहिए।

दक्षिणी दिल्ली की लाल गुंबद बस्टी, जहां ज्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूर के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं, उस अव्यवस्थित क्षेत्र का हिस्सा है, जिसे 'अनौपचारिक क्षेत्र' कहा जाता है। यह चौदहवीं सदी के सूफी संत की मजार से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। यह पंचशील पार्क से भी नज़दीक ही है, जो दिल्ली का पॉश इलाका है। इस भीड़-भाड़ वाली कॉलोनी में रहने वाले अधिकांश परिवारों के घर में शौचालय या नल नहीं हैं। हर सुबह कुछ सामुदायिक शौचालयों के बाहर लंबी कतारें लगती हैं। हालांकि कुछ लोगों को पाइप से पानी मिलता है।

दिसंबर, 2020 में, इस बस्टी की कई महिलाएं थोड़े समय के लिए मुखर हुई थीं। उनमें से कई ने दिल्ली रोजी-रोटी अधिकार अभियान नामक सिविल सोसाइटी समूह द्वारा आयोजित 'भूख सुनवाई' में अपनी बातें रखी थीं। मैंने उनके लाइव वीडियो देखे थे। उन्होंने शहर के कई गरीबों के बीच भोजन के संकट की कठोर वास्तविकता को उजागर किया था, जो अपनी नौकरी खो चुके थे और कोविड-19 महामारी की शुरुआत के साथ गहरे कर्ज में डूब गए थे। तबसे मैं कई बार लाल गुंबद बस्टी जा चुकी हूं। हाल ही में मैं एक बार फिर उस बस्टी में गई।

इस बार भी मैंने जिन लोगों से बात की, उनके मन में सबसे ऊपर भोजन का विषय था। दो बच्चों की मां और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ममता बाई चिंतित थीं। उन्होंने बताया कि वह खाना पकाने के लिए 15 किलोग्राम के खाद्य तेल का कनस्टर लेती हैं, जिसकी कीमत दो साल पहले 2,200 रुपये थी, जो अब बढ़कर 3,000 रुपये हो गई है। और इतना ही नहीं, खाना पकाने के तेल से लेकर सब्जी, रसोई गैर से और दूध—सभी बीजों की कीमतें बढ़ गई हैं।

उनके पड़ोस की एक गृहिणी संजू (जिनके पति वेटर का काम करते हैं और जिनके दो बच्चे हैं) का कहना है कि परिवार के पास कोई बचत नहीं है और खाने—पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। वह इस बात को लेकर चिंतित है कि नए शैक्षणिक वर्ष में बच्चों के स्कूल की फीस के साथ चुकाई जाएगी। उस परिवार ने अपने आहार में सब्जियों की कटौती कर दी है। बच्चों को भी कम दूध दिया जाता है और बड़े लोग कम चाय पीते हैं। वह कहती है कि 'हम अपने मित्रों को ज्यादा आमंत्रित नहीं करते हैं। ऐसे कहां हैं?'

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेरवाई) ने तीव्र भुखमरी को दूर करने में मदद की है। यह गरीबों के लिए केंद्र सरकार की मुफ्त खाद्यान्न योजना है, जिसमें सरकार प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलोग्राम चावल और गेहूँ मुफ्त में देती है। इस योजना से लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलता है और हाल ही में इसे आगामी सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन गरीबों का गुजारा भी सिर्फ गेहूँ या चावल खाने से नहीं होता है। उनकी दूसरी जरूरतें भी हैं।

जब खाने—पीने की चीजों की कीमतें अधिक होती हैं, तो कई लोगों के पास कम खाने या सस्ता और कम गुणवत्ता वाला खाना खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। फिर और भी खर्च हैं और सब पर महंगाई भारी है। परांते बेचने वाली एक बुजुर्ग विधवा ने मुझे बताया कि वह खाना पकाने के लिए एसें दिन भी आते हैं, जब हाथ में पैसे नहीं होते हैं। और वह एक चपती, नमक और थोड़ा अचार खाकर सो जाती है। वह अपने परांतों की कीमत नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि उनके ग्राहक भी बुरे समय से गुजर रहे हैं और अगर वह अधिक पैसे लेंगी, तो वे कहीं और जा सकते हैं।

ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी ने परिवहन लागत के साथ सभी को प्रभावित किया है। जबकि कम बचत और कम सामाजिक सुरक्षा वाले गरीब सबसे बुरी तरह से प्रभावित हैं। मध्यम और निम्न—मध्यम वर्ग के परिवार भी हाल के दिनों में भोजन और ईंधन की कीमतों में तेज वृद्धि के चलते बेहद कठिन समय से गुजर रहे हैं। पिछले तीन वर्षों में कई मध्यम वर्गीय परिवारों ने अपने परिवार के कमाने वाले व्यक्ति को कीमती खोते देखा है कि कई लोग कम कमा रहे हैं और कई कर्ज में भी हैं।

हेरानी की बात नहीं कि लोग कम खरीदारी कर रहे हैं, कम खाना खा रहे हैं और गैर—जरूरी खर्चों में कटौती कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डालते गा। और सबको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर रस्यू-यूक्रेन संचारी जारी रहता है और वैश्विक आपूर्ति शून्खला बाधित रहती है, तो उपमोक्षाओं को आने वाले महीनों में कीमतों के मोर्चे पर और भी अधिक कष्ट सहने के लिए खुदू को तैयार करना चाहिए। खुदरा मुद्रास्फीति के जोखिम अधिक व्यापक होते जा रहे हैं। अन्य संकेत भी परेशान करने वाले हैं।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल मार्च के महीने में अत्यधिक गर्मी ने गेहूँ की फसल को तुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है और इससे गेहूँ की पैदावार में पंद्रह से बीस फीसदी की कमी आ सकती है। फिर रुस के यूक्रेन पर हमले के दुश्यभाव के रूप में गेहूँ नियर्तिकों द्वारा वैश्विक गेहूँ की कीमतों में तेज वृद्धि का फैदा उठाने की बातें की जा रही हैं। सरकार के पास खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है, जिसे खुले बाजार में कीमतों में और वृद्धि होने पर विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए। हर कोई मधुरस्फीति जल्द ही कम नहीं होती है और आर्थिक सुधार में देरी होती है, तो सरकार को सबसे कमज़ोर लोगों को अधिक से अधिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। ऐसे अनिश्चित माहौल में जब मौसम की चरम स्थितियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो हमारे लिए जलवायु परिवर्तन उतना ही महत्वपूर्ण कारक होना चाहिए और खाद्यान्न के बारे में हमारी चर्चा में मौसम की चरम घटनाओं से निपटने की आवश्यकता शामिल होनी चाहिए। संकट की घड़ी में भोजन के बारे में हमारी चर्चा खुशनुमा नहीं होगी, लेकिन हमें इसके बारे में जलवायु परिवर्तन को छोड़कर सबको प्रभावित कर रही है।

यदि खुदरा मुद्रास्फीति जल्द ही कम नहीं होती है और आर्थिक सुधार में देरी होती है, तो सरकार को सबसे कमज़ोर लोगों को अधिक से अधिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। ऐसे अनिश्चित माहौल में जब मौसम की चरम स्थितियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो हमारे लिए जलवायु परिवर्तन उतना ही महत्वपूर्ण कारक होना चाहिए और खाद्यान्न के बारे में हमारी चर्चा में मौसम की चरम घटनाओं से निपटने की आवश्यकता शामिल होनी चाहिए। संकट की घड़ी में भोजन के बारे में खेलकूद करने वाले लोगों को पानी मिलता है कि लेखक के अपने विचार हैं।

मेनका गांधी के संसदीय क्षेत्र में अधोषित विद्युत कटौती से क्षेत्र की जनता त्रस्त

सुलतानपुर व्यूरो आलोक श्रीवास्तव : इन दिनों विद्युत विभाग द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में की जा रही अधोषित विद्युत कटौती से क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त हो रहा है। सुवह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश की विद्युत विभाग जमकर धम्भियाँ उड़ा रही हैं, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे तो शहरी क्षेत्र में 24 घंटे विद्युत सप्लाई का शेल्ड्यूल जारी किया गया था, लेकिन जनता ने विद्युत सप्लाई का शेल्ड्यूल जारी रखा है।

के लोगों में विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों के प्रति आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि आखिर सासद



मेनका गांधी के संसदीय क्षेत्र के लोगों को अधोषित विद्युत कटौती है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य मेले का हुआ आयोजन

जौनपुर व्यूरो विश्वप्रकाश श्रीवास्तव :

जौनपुर व्यूरो विश्वप्रकाश श्रीवास्तव : आज दिनांक 23.04.2022 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक विशाल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यक विद्युत विभाग की तरफ से खंड शिक्षा में 18 व शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे विद्युत सप्लाई का शेल्ड्यूल जारी किया गया था, लेकिन जनता ने विद्युत सप्लाई का शेल्ड्यूल जारी रखा है।

विभाग द्वारा आयोजित स्वास्थ्य मेले का विद्युत विभाग द्वारा लगाए गए स्टालों की लकड़ी सिंह विभाग द्वारा आयोजित स्वास्थ्य मेले का विद्युत विभाग द्वारा लगाए गए स्टालों की लकड़ी विद्युत विभाग द्वारा आयोजित स्वास्थ्य मेले का विद्युत विभाग द्वारा लगाए गए स्टालों की लकड़ी विद्युत विभाग द्वारा आयोजित स्वास्थ्य मेले का विद्युत विभाग द्वारा लगाए गए स्टालों की लकड़ी विद्युत विभाग द्वारा आयोजित स्वास्थ्य मेले का विद्युत विभाग द्वारा लगाए गए स्टालों की लकड़ी विद्युत विभाग द्वारा आयोजित स्वास्थ्य मेले का विद्युत विभाग द्वारा लगाए गए स्टालों की लकड़

